



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2004/श्रावण 22, 1926

No. 715]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2004/SRAVANA 22, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2004

का.आ. 924(अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उप-धारा (7) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपधारा के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के साथ समामेलन की योजना के संबंध में 14 अगस्त, 2004 को निर्धारित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 15/2/2004-बी.ओ.ए.(i)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2004

S.O. 924(E).—In pursuance of sub-section (7) of Section 45 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies the 14th day of August 2004 as the prescribed date in relation to the Scheme for the amalgamation of the Global Trust Bank Ltd. with the Oriental Bank of Commerce which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of said sub-section.

[F. No. 15/2/2004-BOA(i)]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2004

का.जा. 925(अ).— चूँकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उप धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर केन्द्र सरकार ने उक्त धारा की उप धारा (2) के अंतर्गत ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश के संबंध में एक अधिस्थगन-आदेश जारी किया है ;

और चूँकि अधिस्थगन की अवधि के भीतर, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनहित में तथा जमाकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश के ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में समामेलन की एक योजना तैयार की थी ;

और चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना का प्रारूप संबंधित बैंकों को भेज दिया था तथा उक्त योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद योजना को मंजूरी हेतु भारत सरकार के पास भेज दिया था ;

इसलिए अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इसके बाद उल्लिखित शर्तों के अधीन, निम्नलिखित योजना को मंजूरी देती है ।

अध्याय-I**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस योजना को दि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, (ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ समामेलन) योजना, 2004 कहा जाये ।

(2) यह योजना उस तारीख से लागू होगी जिसे केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

2. परिभाषाएं : इस योजना में, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो -

(1) "अधिनियम" का अभिप्राय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) है ।

- (2) "आस्ति खाता" का अभिप्राय वह काल्पनिक खाता है जो अंतरक बैंक की देयताओं को समय-समय पर समायोजित करने के बाद अधिशेष अथवा कमी का पता लगाने के लिए योजना के खंड 5 के उप खंड (2) के अनुसरण में खोला गया हो ।
- (3) "संग्रहण खाता" का अभिप्राय वह काल्पनिक खाता है जो आस्तियों और देयताओं के समायोजन के बाद अंतरक बैंक के सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध होनेवाली राशि का, यदि कोई हो, पता लगाने के प्रयोजन हेतु योजना के पैराग्राफ 7 के अनुसरण में खोला गया हो ।
- (4) "निर्धारित तारीख" का अभिप्राय वह तारीख है जिसे पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करे ।
- (5) "योजना" का अभिप्राय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ समामेलन) योजना , 2004 है ;
- (6) "अंतरक बैंक" का अभिप्राय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड है जा एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश में है ;
- (7) "अंतरिती बैंक" का अभिप्राय ओरियंटल बैंक आफ कामर्स है जो एक नया समनुरूप बैंक है जिसका गठन बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था ;
- (8) यहां प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है परंतु उक्त अधिनियम में जिनकी परिभाषा दी गई है, अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है ।

अध्याय - II

कारोबार, संपत्तियों, आस्तियों और देयताओं का अंतरण

3. आस्तियों और देयताओं का अंतरण तथा उसका सामान्य प्रभाव :

- (1) निर्धारित तारीख को तथा उक्त तारीख से अंतरक बैंक के सभी अधिकार, शक्तियां, दावे, मांगें, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, लाभ, आस्तियां और अचल और सचल संपत्तियां, जिनमें परिसर शामिल हैं, जो

भूधृति (अवधि) की सभी अनुषंगियों और जिस पट्टे या करार के अंतर्गत उन्हें धारित किया गया है उसमें आरक्षित या निहित किराये की राशियों तथा अन्य राशियों और प्रसविदाओं के अधीन हैं, तथा कार्यालय के सभी फर्नीचर, खुले रखे गये उपकरण, संयंत्र, उपकरण और साधन-सामग्री, बहियां, कागजात, लेखन-सामग्री का स्टॉक, अन्य स्टॉक और सामान, स्टॉक, शेयरों और प्रतिभूतियों में सभी निवेश, हाथ में तथा मार्गस्थ सभी प्राप्य बिल, हाथ में समस्त नकदी तथा बैंकों में चालू अथवा जमा खाते (जिसमें मांग अथवा अल्पकालिक सूचना पर देय/प्राप्य धनराशि शामिल है), सोना-चांदी, सभी बही ऋण, बंधक ऋण तथा उनके लिए प्रतिभुओं अथवा किसी गारंटी के लाभ सहित अन्य ऋण, सभी अन्य संपत्ति, अधिकार और परिसंपत्तियाँ, अंतरक बैंक के कारोबार के संबंध में सभी गारंटियों का लाभ, इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन अंतरिती बैंक को अंतरित मानी जायेंगी तथा वे उसकी संपत्तियां और आस्तियां होंगी और निर्धारित तारीख से अंतरक बैंक की सभी देयतायें, शुल्क और बाध्यतायें यहां आगे दी गयी सीमा और ढंग से अंतरिती बैंक की देयतायें, शुल्क और बाध्यतायें होंगी ।

(2) ऊपर दिये गये प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संविदाएं, विलेख, बांड, करार, मुख्तारनामे (पॉवर ऑफ अटॉर्नी), विधि सम्मत प्रतिनिधित्व की मंजूरियां तथा किसी भी स्वरूप के विद्यमान अथवा निर्धारित तारीख से तुरंत पहले प्रभावी अन्य लिखत आगे बतायी गयी सीमा तक और ढंग से अंतरिती बैंक के विरुद्ध या पक्ष में प्रभावी होंगे तथा उन पर इस तरह से कार्रवाई की जायेगी मानो अंतरक बैंक के बजाय अंतरिती बैंक उनकी एक पार्टी हो अथवा मानो वे अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी किये गये हों ।

(3) यदि निर्धारित तारीख को कोई मुकदमा, अपील अथवा किसी भी तरह की कोई अन्य विधिक प्रक्रिया अंतरक बैंक द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अनिर्णीत हो तो वह छोड़ी नहीं जायेगी अथवा रोकी नहीं जायेगी अथवा किसी भी प्रकार से उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वह इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन होगी और अंतरिती बैंक द्वारा अथवा उसके विरुद्ध निष्पादित और प्रवर्तित होगी :

परन्तु शर्त है कि इसमें दिए गए किसी अधिनियम के किसी भी उपबंध अथवा किसी नियम, विनियम, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन किया जाता है अथवा निर्धारित तारीख से पूर्व अंतरणकर्ता बैंक के निदेशक अथवा सचिव, प्रबंधक, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई दण्डनीय अपराध संस्थित किया गया है, तो ऐसे निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के विरुद्ध साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 की प्रयोज्यता में पक्षपात किए बिना ऐसे कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार ही उन्हें दण्ड दिया जाएगा। मानो बैंकिंग कंपनी के रूप में अंतरणकर्ता बैंक को समाप्त नहीं किया गया था।

(4) यदि भारत से बाहर किसी देश के कानून के अनुसार इस योजना के प्रावधान उस देश में स्थित किसी आस्ति अथवा देयता के, जो अंतरक बैंक के कारोबार का या अंतरिती बैंक के दायित्व का भाग हो, अंतरण

अथवा उसको निहित करने के लिए स्वयं में प्रभावी न हों तो ऐसी आस्ति अथवा देयता के संबंध में अंतरक बैंक के मामले निर्धारित तारीख को अंतरिती बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपे गये माने जायेंगे और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी आस्तियों के अंतरण और दायित्वों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के प्रयोजन हेतु सभी शक्तियों का उसी प्रकार इस्तेमाल करेगा जैसे कि वे अंतरक बैंक द्वारा इस्तेमाल की गयी हों। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार के अंतरण को प्रभावी बनाने अथवा निहित करने के प्रयोजन हेतु ऐसे सभी कदम उठायेगा जो भारत से बाहर उस देश के कानून द्वारा अपेक्षित हों और उसके संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अंतरक बैंक की किसी भी आस्ति की वसूली करेगा अथवा उसकी देयता की पूर्ति करेगा तथा शुद्ध आगम राशियों को अंतरिती बैंक को अंतरित करेगा।

4. अंतरक बैंक की बहियां बंद करना और तुलनपत्र तैयार करना :

(1) अंतरक बैंक की बहियां बंद कर दी जायेंगी और उनका तुलन किया जायेगा तथा पहली बार उनका तुलनपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2004 को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति के अनुसार तैयार किया जायेगा और उसके बाद निर्धारित तारीख के ठीक पहले की तारीख को कारोबार बंद करने की स्थिति के अनुसार तैयार किया जायेगा और उक्त तुलनपत्र की लेखा-परीक्षा और उसका प्रमाणीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामित किसी सनदी लेखाकार अथवा सनदी लेखाकारों की किसी फर्म से करवाया जायेगा।

(2) पूर्वगामी पैराग्राफ के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये अंतरक बैंक के तुलनपत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र अंतरक बैंक द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी और उसके बाद अंतरक बैंक को तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाता तैयार करने अथवा उसे सदस्यों को प्रस्तुत करने अथवा कंपनी रजिस्ट्रार को प्रतियां प्रस्तुत करने अथवा तुलनपत्र और खातों पर विचार करने या किसी अन्य प्रयोजन हेतु अथवा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 159 के उपबंधों के पालन के लिए बोर्ड की बैठक या वार्षिक आम सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा उसके बाद अंतरक बैंक के निदेशकों के लिए उक्त कंपनी अधिनियम की धारा 285 की अपेक्षानुसार बैठक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5. आस्तियों का मूल्यन और देयताओं का निर्धारण:-

अंतरक बैंक से परामर्श करके अंतरिती बैंक अंतरक बैंक की आस्तियों का मूल्यन करेगा और अंतरक बैंक की देयताओं की, निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार गणना करेगा, अर्थात् : (1)(क) सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों का मूल्यन निर्धारित तारीख से ठीक एक दिन पहले प्रचलित बाजार दर पर किया जायेगा ;

- (ख) (i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 के प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, निर्धारित तारीख के ठीक एक दिन पहले की स्थिति के अनुसार किया जायेगा ;
- (ii) डाकघर प्रमाणपत्रों, खजाना बचत जमा प्रमाणपत्रों तथा किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों अथवा केन्द्र सरकार की अल्प बचत योजना के अंतर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्रों जैसी केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन उनके अंकित मूल्य अथवा उस तारीख को नकदीकरण योग्य मूल्य, जो भी उच्चतर हो, पर किया जायेगा ;
- (iii) जिस स्थिति में अंतरक बैंक द्वारा धारित जमींदारी उन्मूलन बांडों जैसी किसी सरकारी प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य प्रतिभूति के बाजार मूल्य का, जिसके संबंध में मूलधन का भुगतान किस्तों में किया जाना है, निर्धारण नहीं किया जा सकता अथवा किसी अन्य कारण से बाजार मूल्य को उसका सही मूल्य नहीं माना जा सकता है अथवा अन्यथा उचित नहीं माना जा सकता है, उस स्थिति में उस प्रतिभूति का मूल्यन मूलधन की किस्तों और अदा करने के लिए शेष ब्याज, इस प्रकार की किस्तों के देय रहने की अवधि, जिस सरकार की प्रतिभूति हो उस सरकार द्वारा जारी की गयी उसी अवधि की अथवा लगभग उसी अवधि की किसी प्रतिभूति पर प्राप्य प्रतिफल तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए उचित समझी गयी राशि के अनुसार किया जायेगा ;
- (ग) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड अथवा अन्य निवेश का बाजार मूल्य असामान्य बातों द्वारा प्रभावित होने के कारण उचित नहीं माना जा सकता है, वहां ऐसे निवेश का मूल्यन किसी उचित अवधि में उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा ;
- (घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड अथवा अन्य निवेश का बाजार मूल्य निर्धारण योग्य नहीं है, वहां केवल उसी मूल्य को, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाएगा जिसे ऐसी प्रतिभूतियों इत्यादि को जारी करनेवाले प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, पिछले पांच वर्षों में अदा किये गये लाभांश तथा अन्य प्रासंगिक बातों को भी ध्यान में रखते हुए उचित माना जाये ;
- (ङ) दावों को पूरा करने के लिए अभिग्रहीत परिसरों तथा अन्य सभी अचल संपत्तियों और आस्तियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर किया जायेगा ;
- (च) फर्नीचर और फिक्स्चर, स्टॉक में उपलब्ध लेखन-सामग्री तथा अन्य आस्तियों, यदि कोई हों, का मूल्यन बहियों में लिखे गये हासित मूल्य पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर, जैसा भी उपयुक्त समझा जाये, किया जायेगा ;

- (छ) अंतरिती बैंक खरीदे और भुनाये गये बिलों सहित अग्रिमों, बही-ऋणों और विविध आस्तियों की संवीक्षा करेगा और प्रतिभूतियों और उनके जोखिमों को पूरा करने के लिए दी गयी गारंटियों की जांच और सत्यापन करेगा । उसके बाद अग्रिमों को उनके अंशों सहित, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा अर्थात् "लाभकर और तत्काल वसूलीयोग्य समझे गये अग्रिम" और "तत्काल वसूली योग्य न माने जानेवाले अथवा वसूली के लिए अशोध्य और संदिग्ध समझे गये अग्रिम" ।
- (2) अंतरिती बैंक निर्धारित तारीख को "आस्ति खाता" के रूप में एक खाता खोलेगा । इस खंड के अनुसार तत्काल वसूलीयोग्य आस्तियों के रूप में निर्धारित आस्तियों के मूल्य से संबंधित कुल राशि "आस्ति खाते" में जमा की जायेगी ।
- (3) (i) जहां किसी आस्ति का मूल्यन निर्धारित तारीख को निश्चित नहीं हो सकता, वहाँ उसे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, बाद की तारीख को अंशतः या पूर्णतः वसूली योग्य आस्ति माना जायेगा ;
- (ii) किसी आस्ति के मूल्यन अथवा किसी अग्रिम के वर्गीकरण अथवा किसी देयता के निर्धारण के संबंध में अंतरिती बैंक और अंतरक बैंक के बीच असहमति की स्थिति होने पर उक्त मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जायेगा, परंतु ऐसी राय प्राप्त होने तक उक्त मद या उसके किसी भाग का मूल्यन इस योजना के प्रयोजनों के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अनंतिम रूप में स्वीकार किया जायेगा ;
- (iii) रिजर्व बैंक के लिए यह उचित होगा कि यदि ऐसा करना उसके लिए आवश्यक हो तो वह आस्ति की किसी ऐसी मद के मूल्यन या देयता की किसी ऐसी मद के मूल्य-निर्धारण के संबंध में उपयुक्त समझा गया कोई तकनीकी परामर्श प्राप्त करे और ऐसा परामर्श प्राप्त करने की लागत पूर्णतया अंतरक बैंक की आस्तियों में से देय होगी ।
- (4) देयता का निर्धारण: इस योजना के प्रयोजनों के लिए देयताओं में वे सभी प्रासंगिक देयताएं शामिल होंगी जिन्हें निर्धारित तारीख को या उसके बाद उपयुक्त रूप से उसके अपने संसाधनों से पूरा करने की अंतरिती बैंक से अपेक्षा की जायेगी ।
- (5) पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार किया गया आस्तियों का मूल्यन और देयताओं का निर्धारण दोनों बैंकों और उनके सदस्यों तथा ऋणदाताओं के लिए बाध्यकर होगा ।

अध्याय - III

ऋणदाताओं को और जमाकर्ताओं को भुगतान

6. अंतरक बैंक की देयता का निपटान :- (1) निम्नलिखित के संबंध में -

(क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा उस बैंक में स्टाफ-जमानत के रूप में जमा की गयी किसी भी राशि का, निर्धारित तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, यदि कोई हो, पूर्ण भुगतान किया जायेगा या उसके लिए प्रावधान किया जायेगा ;

(ख) सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक जमा, मांग या अल्प सूचना पर देय जमाराशि अथवा कोई भी अन्य जमाराशि, चाहे जिस नाम से हो, सहित अंतरक बैंक के पास स्थित प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते के संबंध में अंतरिती बैंक निर्धारित तारीख को तदनुरूप और उसी तरह का खाता संबंधित धारक (धारकों) के नाम से खोलेगा और इस योजना के अंतर्गत देय सीमा तक ब्याज सहित पूर्ण राशि उसके खाते में जमा करेगा :

परंतु यह शर्त है कि जहां अंतरिती बैंक को किसी विशेष खाते में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता के संबंध में उचित संदेह हो, वहां वह रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से उस खाते में जमा (क्रेडिट) देने को निर्धारित तारीख से अधिक-से-अधिक तीन महीने के लिए रोक सकता है और इस अवधि में अंतरिती बैंक ऐसे खाते में सही शेष राशि का पता करेगा ।

(2) पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (4) के अंतर्गत तय की गयी अंतरक बैंक की किसी भी अन्य देयता के संबंध में अंतरिती बैंक ऋणदाताओं को ऐसी देयता की राशि का भुगतान देय होने पर करेगा ।

(3) ब्याज वाले किसी भी जमा खाते के संबंध में अंतरिती बैंक रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार लागू दर पर ब्याज निर्धारित तारीख तक अदा करेगा । किसी चालू खाते या बिना ब्याज वाले किसी अन्य खाते की शेष राशियों के संबंध में खातेदार को कोई ब्याज अदा नहीं किया जायेगा । कोई भी खातेदार 25 जुलाई, 2004 से निर्धारित तारीख तक की अवधि के दौरान अपने खाते से किसी जमाराशि या किसी अन्य धन के भुगतान न हो पाने के लिए किसी क्षतिपूर्ति के दावे का हकदार नहीं होगा ।

(4) किसी संविदा में इसके विपरीत कुछ होते हुए भी, चाहे वह स्पष्ट वर्णित हो या निहितार्थ हो, अंतरिती बैंक में खोले गये किसी भी नये खाते के संबंध में ब्याज निर्धारित तारीख से केवल उसी दर पर दिया जायेगा,

जिस दर पर अंतरिती बैंक अपने जमाकर्ताओं को ऐसे खातों पर सामान्यतः ब्याज देता है और योजना के उपबंधों के अनुसार ब्याज जमा (क्रेडिट) किया जायेगा ।

(5) “आस्ति खाते” में जमा शेष का विनियोजन इस पैराग्राफ के अंतर्गत अपेक्षित देयता को पूरा करने के लिए किया जायेगा । आस्ति खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने पर कमी की राशि अंतरिती बैंक द्वारा व्यय की गयी राशि मानी जायेगी और जहां तक संभव होगा, योजना के पैराग्राफ 7 के उप पैराग्राफ (7) में बताये गये अनुसार वसूल की जायेगी ।

अध्याय IV

7. अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार और दायित्व:- (1) इस योजना के शुरू होने पर अंतरक बैंक की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधियों की संपूर्ण राशि अंतरक बैंक के अशोध्य और संदिग्ध तथा अन्य आस्तियों में मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधान के रूप में मानी जायेगी ।

(2) अंतरक बैंक में प्रत्येक शेयर के संबंध में उस राशि को, जिसे निर्धारित तारीख से ठीक एक दिन पहले, प्रत्येक शेयरधारक द्वारा या उसकी ओर से शेयर पूंजी के लिए अदा किया गया माना गया था या नीचे उप पैराग्राफ (4) के अनुसरण में अंतरिती बैंक द्वारा मांगी गयी राशि के रूप में शेयर पूंजी हेतु अदा किया गया माना गया था, उसे “संग्रहण लेखे” के रूप में माना जायेगा और अंतरिती बैंक की बहियों में उसे उसी रूप में दर्ज किया जायेगा ।

(3) अंतरिती बैंक उस प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्धारित तारीख को अंतरक बैंक के साधारण शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत था (अथवा इस रूप में पंजीकृत करने के लिए पात्र माना गया होता)

यथा निर्धारित तारीख अथवा तारीखों से तीन महीने में ऐसे शेयर अथवा शेयरों या बकाया मांग राशि, यदि कोई हो, के संबंध में उसके द्वारा अदत्त रही मांगी न गयी राशि अदा करने को कहेगा ।

(4) अंतरिती बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चूक की अवधि के लिए छः प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित उप पैराग्राफ (3) के अंतर्गत देय राशियों की मांग और भुगतान करने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा ।

(5) अंतरिती बैंक अग्रिमों, खरीदे और भुनाये गये बिलों, बही ऋणों और विविध ऋणों तथा अन्य आस्तियों के संबंध में, जिन्हें ‘आसानी से न वसूले जाने योग्य अग्रिम’ या वसूली के लिए अशोध्य और

संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या जो निर्धारित तारीख के बाद पूर्णतः या अंशतः वसूलीयोग्य हैं या हो सकते हैं, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मांग और भुगतान करने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा और -

(क) देनदार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ समझौता या व्यवस्था करेगा या ऐसे ऋण या आस्ति को बड़े खाते डालेगा ;

(ख) उसे अंतरित की गयी किसी प्रतिभूति या उसके द्वारा ली गयी किसी आस्ति की बिक्री करेगा या अन्य प्रकार से निपटान करेगा ।

(6) इसके अलावा, अंतरिती बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45ज के साथ पठित धारा 45ठ तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 543 के अंतर्गत अंतरक बैंक के किसी प्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्षति के रूप में अधिनिर्णीत की गयी राशि की, यदि कोई हो, मांग या भुगतान करने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सभी उपाय करेगा ।

(7) अंतरिती बैंक उप पैराग्राफ (4), (5) और (6) में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्र. को गयी वसूलियों में से पहले तो वसूली के लिए किये गये खर्च के लिए विनियोजन करेगा और उसके बाद पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (5) में उल्लिखित कमी के लिए विनियोजन करेगा । इस प्रकार के विनियोजन के बाद यदि कोई अधिशेष बचेगा तो अंतरिती बैंक किसी आकस्मिक देयता तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य देयता, चाहे आकस्मिक हो अथवा समग्र, जिसका अनुमान पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (4) में नहीं लगाया गया था और वह देयता निर्धारित तारीख के बाद बनी या पता लगी हो, के लिए भुगतान करेगा या प्रावधान करेगा ।

(8) उप पैराग्राफ (7) में उल्लिखित मदों के लिए विनियोजन के बाद यदि कोई अधिशेष राशि बचेगी तो अंतरिती बैंक उस राशि में से अंतरक बैंक के पहले के शेयरधारकों के कारण राशि का समानुपातिक भुगतान करेगा । यह भुगतान नीचे बताये गये ढंग से और निर्दिष्ट सीमा तक होगा : -

(क) पहले तो अंतरक बैंक के अधिमान शेयरधारकों को देय राशियों, यदि कोई हों, के लिए तब तक भुगतान करेगा, जब तक सभी खातों के बारे में पूरा भुगतान न हो जाये ;

(ख) उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित राशियों का पूर्ण भुगतान हो जाने के बाद यदि कोई अधिशेष राशि अंतरिती बैंक के हाथ में बचेगी तो उसका समानुपातिक रूप से वितरण अंतरक बैंक के साधारण शेयरधारकों के बीच किया जायेगा :

परंतु यह शर्त है कि यदि यह प्रश्न कि क्या उपर्युक्त उप पैराग्राफों में उल्लिखित खातों से कोई राशि मिलनी है तो मामला रिजर्व बैंक को उसके निर्णय हेतु भेजा जायेगा।

(9) इस खंड में उल्लिखित संग्रहण खातों को देय राशियां अंतरिती बैंक की देयताएं उसी सीमा तक मानी जायेंगी, जिस सीमा तक इस योजना में प्रावधान है।

(10) निर्धारित तिथि से बारह साल की समाप्ति पर अथवा ऐसी पूर्व अवधि में जैसा केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे, इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (5) में निर्दिष्ट किसी ऐसी मद का, जिसकी वसूली उस तारीख तक न की गयी हो, मूल्यांकन अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा तथा अंतरिती बैंक उस मूल्यांकन में निर्धारित किसी राशि या राशियों का वितरण पहले पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (4) में निर्दिष्ट देयताएं पूरी करने के लिए आवश्यक ऐसी किसी राशि की, जो उस तारीख को पूरी न की जा सकी हो, कटौती करने के बाद उपर्युक्त उप पैराग्राफ (8) में उल्लिखित क्रम और पद्धति से करेगा।

अध्याय V

अंतरक बैंक के कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व

8. कर्मचारियों की सेवा जारी रखना :- (1) अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी (उन कर्मचारियों को छोड़कर जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) के अर्थों में कामगार श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं तथा जिनके नाम अनुसूची क में उल्लेख किये गये हैं) सेवा में बने रहेंगे तथा यह माना जायेगा कि उन्हें अंतरिती बैंक में उन्हीं परिलब्धियों तथा सेवा संबंधी शर्तों पर नियुक्त किया गया है, जो 24 जुलाई, 2004 को कारोबार की समाप्ति से ठीक पहले उन कर्मचारियों पर लागू थीं :

परंतु शर्त यह है कि अंतरक बैंक के जो कर्मचारी योजना की मंजूरी की तारीख जो, जिस दिन केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना की मंजूरी की गई है, के बाद एक माह की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय अंतरक बैंक अथवा अंतरिती बैंक को लिखित नोटिस द्वारा अंतरिती बैंक के कर्मचारी न बनने का अपना इरादा व्यक्त करें, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अंतर्गत ऐसी क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, तथा ऐसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति विषयक अन्य प्रकार के लाभों के हकदार होंगे जो 24 जुलाई, 2004 को कारोबार की समाप्ति से तुरंत पहले लागू अंतरक बैंक के नियमों या प्राधिकारों के अंतर्गत सामान्यतः उन्हें प्राप्त होते।

(2) अंतरक बैंक के जिन कर्मचारियों को अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त माना गया हो, उनके संबंध में यह भी माना जायेगा कि अंतरिती बैंक ने उनकी छंटनी संबंधी क्षतिपूर्ति का दायित्व भी ले लिया है। उस स्थिति में जब अंतरिती बैंक की सेवा में रहते हुए उनकी छंटनी की जाए तो क्षतिपूर्ति का हिसाब इस आधार पर होगा कि उनकी सेवाएं निरंतर बनी रही थी और अंतरिती बैंक में उनके स्थानांतरण के कारण उनमें कोई व्यवधान नहीं आएगा।

(3) उप पैराग्राफ (1) के परंतुक के अंतर्गत सेवा में न रहने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अन्य जिन कर्मचारियों की सेवाएं उप पैराग्राफ (1) के अंतर्गत अंतरिती बैंक में जारी रहेंगी उन्हें अंतरिती बैंक इस योजना की स्वीकृति की निर्धारित तारीख से तीन वर्ष से अधिक अवधि के भीतर वही परिलब्धियां अदा करेगा तथा वही सेवा शर्तें प्रदान करेगा जो अंतरिती बैंक के उसी श्रेणी या स्तर के तदनु रूपी कर्मचारियों पर लागू होंगी, परंतु शर्त यह होगी कि अंतरक बैंक के उक्त कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव अंतरिती बैंक के अन्य समकक्ष कर्मचारियों के समान हों :

परन्तु यह शर्त है कि यदि इस संबंध में कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो कि क्या उपर्युक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी की योग्यता अथवा अनुभव अंतरिती बैंक के उसी श्रेणी या उसी स्तर के अन्य कर्मचारियों की योग्यता तथा अनुभव के जैसा अथवा समकक्ष है या नहीं अथवा अंतरिती बैंक के वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के लिए अपना जाने वाले सिद्धांतों अथवा प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो तो ऐसे संदेह अथवा मतभेद को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(4) अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि और उपदान के न्यासी अथवा प्रशासक अथवा, यथास्थिति, अंतरक बैंक, निर्धारित तारीख को अथवा निर्धारित तारीख के बाद यथाशीघ्र

अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और उपदान निधि के न्यासियों को अथवा अन्य प्रकार से, जैसा भी अंतरिती बैंक निर्देश दे, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लाभार्थ न्यास में रखे हुए सारे धन एवं निवेशों को अंतरित कर देंगे :

परन्तु यह शर्त है कि ऐसे परवर्ती न्यासी, योजना आरंभ होने से पूर्व निवेशों के मूल्य में हुई किसी कमी अथवा किये गये किसी कार्य, उपेक्षा अथवा चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे ।

अध्याय VI

विविध

9. जमाकर्ताओं अथवा ऋणदाताओं द्वारा मांग :- अंतरक बैंक का कोई भी जमाकर्ता अथवा ऋणदाता अंतरक बैंक अथवा अंतरिती बैंक के विरुद्ध उसके प्रति अंतरक बैंक की किसी देयता के संबंध में ऐसी कोई भी मांग करने का हकदार नहीं होगा जो इस योजना द्वारा निर्धारित न हो ।

10. केन्द्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरिती या अंतरक बैंक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही :-

इस योजना के अनुसरण में सद्भाव से की गयी अथवा की जानेवाली किसी बात के लिए केन्द्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अंतरिती बैंक या अंतरक बैंक के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं लाया जाएगा अथवा कानूनी कार्यवाई नहीं की जायेगी ।

11. अंतरक बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन :- अंतरिती बैंक को यह विकल्प होगा कि वह अपनी सुविधा के अनुसार अंतरक बैंक की शाखाओं का समेकन करे और अंतरक बैंक की हानि पर चल रही वर्तमान शाखाओं को बंद कर दे अथवा स्थानांतरित कर दे । तथापि यह विकल्प अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर अपनाया जायेगा ।

12. विवरण तथा जानकारी देना :- अंतरिती बैंक इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले विवरण तथा जानकारी केन्द्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा ।

- 13. सूचना (नोटिस) देने का तरीका :-** जब तक कि अंतरिती बैंक की बहियों में नया पता दर्ज न हो, तब तक अंतरिती बैंक द्वारा दिये जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस अथवा अन्य सूचना यदि अंतरक बैंक की बहियों में दर्ज पते पर स्पीड पोस्ट, कूरियर, पूर्व अदायगी वाली सामान्य डाक अथवा अन्य माध्यम से प्रेषिती को संबोधित हो एवं भेजी गयी हो तो वह विधिवत् दी गयी सूचना मानी जायेगी तथा ऐसा नोटिस डाक द्वारा भेजे जाने के चार दिन के बाद मिला हुआ माना जाएगा। साथ ही, सामान्य हित का कोई नोटिस अथवा सूचना एक या अधिक ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायेगी जो कि उन स्थानों पर परिचालन में होंगे जहां अंतरक बैंक अपना कारोबार कर रहा था।

[फा. सं. 15/2/2004-बी.ओ.ए.(ii)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2004

S.O. 925(E).—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government has made, under sub-section (2) of that section an order of Moratorium in respect of the Global Trust Bank Limited, Secunderabad, Andhra Pradesh;

And whereas during the period of Moratorium, the Reserve Bank of India, being satisfied that in public interest and in the interest of the depositors so to do, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 45 of the said Act had prepared a Scheme for the amalgamation of the Global Trust Bank Limited with the Oriental Bank of Commerce;

And whereas the Reserve Bank of India, after having sent the said Scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme, had forwarded it to the Central Government for sanction;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the following scheme on and subject to the terms and conditions hereafter mentioned.

Chapter -1

Preliminary

1. **Short title and commencement :-** (1) The Scheme may be called the Global Trust Bank Limited (Amalgamation with Oriental Bank of Commerce) Scheme, 2004.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify.
2. **Definitions:-** In the Scheme, unless the context otherwise requires --
 - (1) "Act" means the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
 - (2) "Asset Account" means a notional account opened pursuant to sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Scheme for the purpose of ascertaining the surplus or shortfall after the adjustment from time to time of liabilities of the transferor bank as provided in the Scheme;
 - (3) "Collection Account" means a notional account opened in accordance with paragraph 7 of the Scheme, for the purpose of ascertaining the amount, if any, available for distribution to the members of the transferor bank after adjustment of assets and liabilities;
 - (4) "prescribed date" means the date which the Central Government may specify under sub-paragraph (2) of paragraph 1;
 - (5) "Scheme" means the Global Trust Bank Limited (Amalgamation with Oriental Bank of Commerce) Scheme, 2004;
 - (6) "transferor bank" means the Global Trust Bank Limited, a banking company having its Registered Office at Secunderabad, Andhra Pradesh;
 - (7) "transferee bank" means the Oriental Bank of Commerce, being a corresponding new bank constituted under section 3 of the **Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980)**;
 - (8) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Chapter - II.

Transfer of business, properties, assets and liabilities

3. Transfer of assets and liabilities and general effect thereof :- (1) On and from the prescribed date, all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved or contained in the leases or agreements under which they are held, all office furniture, loose equipments, plant apparatus and appliances, books, papers, stocks of stationery, other stocks and stores, all investments in stocks, shares and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit accounts (including money at call or short notice) with banks, bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefits of securities, or any guarantee therefor, all other, if any, property rights and assets, benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of the Scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of the transferee bank; and on and from the prescribed date, all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the manner provided hereinafter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

(3) If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall, subject to the other provisions of the Scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank :

Provided that where a contravention of any of the provisions of any Act or of any rule, regulation, direction or order made thereunder has been committed by, or any proceeding for a criminal offence has been instituted against, a director or secretary, manager, officer or other employee of the transferor bank before the prescribed date, such director, secretary, manager, officer or other employee shall, without prejudice to the application of section 6 of the General Clauses Act, 1897, be liable to be proceeded against under such law and punished accordingly as if the transferor bank, being a banking company had not been dissolved.

(4) If according to the laws of any country outside India, the provisions of the Scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such asset or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank and the Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively transferring such assets and discharging such liabilities. The Chief Executive Officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith, the Chief Executive Officer may, either himself or through any person authorized by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

4. Closure of books of the transferor bank and preparation of balance sheet:- (1) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheet prepared in the first instance as at the close of business on the 24th July, 2004 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance sheet shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

24976J104-3

(2) A copy of the balance sheet of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheet or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any board meeting or annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of section 159 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by section 285 of that Act.

5. Valuation of assets and determination of liabilities:- The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely:-

(1) (a) Investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date;

(b) (i) the Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the principles laid down in the notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(ii) the Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher;

(iii) where the market value of any Government Security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security if any held by the transferor bank in respect of which the principal is payable in installments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such amount as is

considered reasonable having regard to the installments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such installments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors;

(c) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;

(d) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investments is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors;

(e) premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value;

(f) the furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realizable value as may be considered reasonable;

(g) advances, including bills purchased and discounted, book debts and sundry assets, will be scrutinized by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank. Thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories, namely, "Advances considered good and readily realizable" and "Advances considered not readily realizable or bad or doubtful of recovery".

(2) The transferee bank shall open on the prescribed date an account styled as "Asset Account". The aggregate amount representing the value of the assets determined as readily realisable assets in accordance with this paragraph shall be credited to the "Asset Account".

- (3) (i) Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India, be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date;
- (ii) in the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regard the valuation of any asset or the classification of any advance or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, for its opinion, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of the Scheme;
- (iii) it shall be competent for the Reserve bank of India, in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

Determination of liability :- Liabilities for purposes of the Scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

- (5) The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

Chapter III

Payment to creditors and depositors

6. Discharge of liability of the transferor bank:-(1) In respect of:

- (a) any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits, together with interest, if any, accrued thereon upto the prescribed date shall be paid or provided for in full;
- (b) every savings bank account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call

or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor bank, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable under the Scheme:

Provided that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Reserve Bank of India withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the prescribed date within which the transferee bank shall ascertain the correct balance in such account.

(2) In respect of every other liability of the transferor bank determined under sub-paragraph (4) of paragraph 5, the transferee bank shall pay to the creditors the amount of such liability as and when they fall due.

(3) In respect of any interest bearing deposit accounts, the transferee bank shall pay interest at the rate applicable in accordance with the directives of the Reserve Bank of India till the prescribed date. In respect of balances in any current account or any other non-interest bearing account, no interest shall be payable to the account holder. No account holder shall be entitled to claim any compensation for the non-payment of any deposit or other money from his account during the period from the 25th July, 2004 till the prescribed date.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest from the prescribed date shall be paid in respect of the new account opened with the transferee bank and credited in accordance with the provisions of the Scheme only at such rates as the transferee bank normally allows to its own depositors for such accounts.

(5) The credit balance in the "Asset Account" shall be appropriated to the extent required to meet the liability under this paragraph. If the balance in the Asset Account is not sufficient, so much of the shortfall shall be treated as amount spent by the transferee bank and to the extent possible, be recovered by it as provided in sub-paragraph (7) of paragraph 7.

Chapter IV

- 7. Rights and liabilities of the members of the transferor bank:-** (1) On the commencement of the Scheme, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank.
- (2) In respect of every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date or the amount paid on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of sub-paragraph (4) below shall be treated as a "Collection Account" and shall be entered as such in the books of the transferee bank.
- (3) The transferee bank shall call upon every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any.
- (4) The transferee bank shall take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under sub-paragraph (3) above together with interest at six percent per annum for the period of the default.
- (5) The transferee bank shall in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realizable or bad or doubtful of recovery " or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, and may -
- (a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset;

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(6) The transferee bank shall, in addition, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under section 45L, read with section 45H of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and also with section 543 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(7) The transferee bank may appropriate the realisations effected by it on account of the items mentioned in sub-paragraphs (4), (5) and (6), in the first instance towards expenses incurred for the recovery of such amount and thereafter towards the shortfall referred to in sub-paragraph (5) of paragraph 6. If any surplus remains after such appropriation, the transferee bank shall make payment or provision in respect of any contingent liability as also with the prior approval of the Reserve Bank of India, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of sub-paragraph (4) of paragraph 5 and has arisen or been discovered after the prescribed date.

(8) If any surplus remains after the appropriation in terms of sub-paragraph (7), the transferee bank shall, make payments pro-rata from amount if any available towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below :-

- (a) in the first place, the amounts, if any, due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;
- (b) after all the amounts mentioned in sub-paragraph (a) have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed pro-rata among the former ordinary shareholders of the transferor bank.

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-paragraphs, it shall be referred to the Reserve Bank of India for its decision.

(9) The amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in the Scheme.

(10) On the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in sub-paragraph (5) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any amount or amounts determined in the light of that valuation, after deducting therefrom first any such amount necessary for meeting the liabilities referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 5 which may remain unsatisfied as on that date, in the order and the manner provided in sub-paragraph (8).

Chapter V

Rights and obligations of the Employees of Transferor Bank

8. Continuation of services of the employees:- (1) All the employees of the transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed in the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, as were applicable to such employees immediately before the close of business on the 24th July, 2004.

Provided that the employees of the transferor bank, who have by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the prescribed date on which the Scheme has been sanctioned by the Central Government, intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules or

authorisations of the transferor bank as in force immediately before the close of business on the 24th July, 2004.

(2) The transferee bank shall, in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank, be deemed also to have taken over the liability for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their services have been continuous and have not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(3) The transferee bank shall, not later than the expiry of the period of three years from the date on which the scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank whose services are continued in the transferee bank under sub-paragraph (1), except such of the employees who cease to be in service under the proviso to sub-paragraph (1), the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank:

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure or principles to be adopted for the fixation of pay of the said employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(4) The trustees or administrators of any provident fund and gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank, or as the case may be, the transferor bank, shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustees of the employees' provident fund and gratuity fund constituted for the transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all the moneys and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank :

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect or default done before the date of commencement of the Scheme.

Chapter VI

Miscellaneous

- 9. Demand by Depositors or Creditors:-** No depositor or creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by the Scheme.
- 10. Legal proceedings against the Central Government, Reserve Bank of India, Transferee or Transferor bank:-** No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee bank or the transferor bank for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the Scheme.
- 11. Reorganisation of branches of transferor bank:-** The transferee bank shall have the option of integrating branches of transferor bank according to its convenience and may close down or shift the existing loss making branches of the transferor bank. The aforesaid option will, however, be exercised by the transferee bank with the prior approval of Reserve Bank of India, within a period of one year.
- 12. Furnishing statement and information:-** The transferee bank shall submit to the Central Government and Reserve Bank of India such statements and information as may be required by the Central Government and Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of the Scheme.
- 13. Manner of service of notice:-** Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by speed post or by courier or by pre-paid ordinary post or otherwise to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of four days

after it has been posted. Any notice or communication, which is of general interest shall be advertised, in addition, in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

[F. No. 15/2/2004-BOA(ii)]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.